While pharmaceuticals is a chemical product in one sense, we are cautious now, compared to the time when the Union Carbide incident happened. I think the Union Carbide incident is an accident. Undoubtedly, we have to be cautious. We have put in place many more regulatory framework, as far as safety and environment is concerned, from 1985....

MR. CHAIRMAN: Okay, that is all right.

SHRI KAMAL NATH: ...when the Union Carbide tragedy happened. I think much water, in the last 20 years, flowed under the birdge. But we are conscious...

MR. CHAIRMAN: That is enough.

SHRI KAMAL NATH: ... as you said, about safety.

MR. CHAIRMAN: The Members are very much satisfied with your reply.

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना

*472. **श्री मोती लाल वोरा:†**
श्रीमती प्रेमा करियप्पा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिन गांवों को सड़क से जोड़ा गया है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितनी लंबी सड़क का निर्माण किया गया; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क संपर्क की इकाई ''बसावट'' होती है। वर्ष 2001-03, 2003-04 तथा 2004-05 में स्वीकृत प्रस्तावों में से जिन बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया जाएगा, उनकी राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई हैं (नीचे **देखिए**) चूंकि वर्ष 2001-2 तथा 2002-3 के लिए प्रस्ताव एक साथ मंजूर किए गए थे, इसलिए वर्ष 2002-03 के लिए अलग से कोई कवरेज आंकड़े नहीं हैं।

---

†सभा में यह प्रश्न मोती लाल वोरा द्वारा पूछा गया।

(ख) और (ग) 2001-03, 2003-04 और 2004-05 में छत्तीसगढ़ के संबंध में निर्माण के लिए स्वीकृत सड़कों की कुल लंबाई 5589.44 कि.मी. है जिसमें से 1805 कि.मी. सड़कों का निर्माण हो चुका है। इन सड़कों के निर्माण पर मार्च, 2005 के अंत तक हुआ खर्च 495.54 करोड़ रु० है।

विवरण-I

बसावटों की संख्या जिन्हें चरण-II (2001-03), चरण-III (2003-04), चरण-IV (2004-05), में स्वीकृत पीएमजीएसवाई प्रस्तावों से सड़कों से जोड़ा जाएगा।

क्र सं०	राज्य	कवर की जाने वाली कुल बसावटें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	774
2.	अरूणाचल प्रदेश	84
3.	असम	1871
4.	बिहार	1164
5.	छत्तीसगढ़	1881
6.	गोवा	20
7.	गुजरात	940
8.	हरियाणा	0
9.	हिमाचल प्रदेश	832
10.	जम्मू और कश्मीर	241
11.	झारखंड	810
12.	कर्नाटक	241
13.	केरल	361
14.	मध्य प्रदेश	2583
15.	महाराष्ट्र	841
16.	मणिपुर	0
17.	मेघालय	98
18.	मिजोरम	63
19.	नागालैंड	40
20.	उड़ीसा	2026
21.	पंजाब	339
22.	राजस्थान	3646

1	2	3
23.	सिक्किम	47
24.	तमिलनाडु	1055
25.	त्रिपुरा	208
26.	उत्तर प्रदेश	4000
27.	उत्तरांचल	205
28.	प॰ बंगाल	2459
	कुल	26829

National Rural Road Scheme

†*472. SHRI MOTILAL VORA:††
SHRIMATI PREMA CARIAPPA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the State-wise details of villages having been linked up with the roads under the National Rural Road Scheme during the last three years;

(b) the total length of roads constructed in the State of Chhattisgarh during this period; and

(c) the expenditure incurred thereon?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The unit for connectivity under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) is 'habitation'. The number of habitations State-wise that would get connectivity out of proposals cleared in the years 2001-03, 2003-04 and 2004-05 are given in the Statement-I (*See* below). Since proposals for 2001-02 and 2002-03 were cleared together, there are no separate coverage figures for the year 2002-03.

(b) and (c) The total length of roads cleared for construction in respect of Chhattisgarh in the years 2001-03, 2003-04 and 2004-05 is 5589.44 kms., out of which 1805 kms. have been completed. The expenditure incurred upto end of March, 2005 in respect of these roads is Rs. 495.54 crore.

†Original notice of the question was received in Hindi.

††This question was actually asked on the floor of the House by Shri Moti Lal Vora.

Statement-I

Number of Habitations that would get connectivity out of PMGSY proposals cleared in Phase-II (2001-03), Phase-III (2003-04) & Phase-IV (2004-05)

Sl.No.	States	Total habitations being covered (2001-03 to 2004-05)
1.	Andhra Pradesh	774
2.	Arunachal Pradesh	84
3.	Assam	1871
4.	Bihar	1164
5.	Chhattisgarh	1881
6.	Goa	20
7.	Gujarat	940
8.	Haryana	0
9.	Himachal Pradesh	832
10.	Jammu & Kashmir	241
11.	Jharkhand	810
12.	Karnataka	241
13.	Kerala	361
14.	Madhya Pradesh	2583
15.	Maharashtra	841
16.	Manipur	0
17.	Meghalaya	98
18.	Mizoram	63
19.	Nagaland	40
20.	Orissa	2026
21.	Punjab	339
22.	Rajasthan	3646
23.	Sikkim	47
24.	Tamil Nadu	1055
25.	Tripura	208
26.	Uttar Pradesh	4000
27.	Uttaranchal	205
28.	West Bengal	2459
	TOTAL	**26829**

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, सन् 2001 से लेकर 2005 तक 5589.44 किलोमीटर में से 1805 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और इसके लिए जो धनराशि

स्वीकृत हुई है, वह 495.54 करोड़ रुपए की है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने इन सड़कों की लंबाई में कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा? मुख्य रूप से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो बसावट के गांव हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने गांवों को इस सड़क के अंतर्गत जोड़ा गया है? माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, प्रश्नोत्तर में ही स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ का कुल 1881 हैबिटेशन्स से जोड़ा गया है। माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके उत्तर में यही है कि इसके अंतर्गत 1881 टोलों को जोड़ा गया है।

श्री मोती लाल वोरा: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 1882 गांवों को आपने जोड़ा है, उसकी जानकारी देने की कृपा करें और इसके साथ ही जो गांव शेष बच गए हैं, क्या सन् 2005 तक उनमें सड़क निर्माण का काम पूरा हो सकेगा?

श्री सभापति: ठीक है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, महोदय।

श्री सभापति: बस ठीक है। हो गया। इतना ही काफी है।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Mr. Chairman, Sir, through you I would like to know from the hon. Minister: What is the exact number of villages in Karnataka which require road connectivity? What is the number of villages covered phase-wise? I want phase-wise break-up. I would also like to know whether by the end of the Tenth Plan Period, all the villages in the State would get road connectivity?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, फेसवाइज़ तो दे दिया गया है ...(*व्यवधान*)...

श्री सभापति: उन्होंने शायद प्रश्न के जवाब को पढ़ा नहीं है।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: I want to know from the hon. Minister whether by the end of the Tenth Plan Period all the villages in the State would get road connectivity?

श्री सभापति: यह है क्वेश्चन।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, 500 से ज्यादा आबादी के ज़ोन्स को जोड़ने का लक्ष्य शुरू में रखा गया था, अब 'भारत निर्माण' के तहत, महोदय, चार वर्षों में 1,000 से ज्यादा आबादी के गांवों को जोड़ने का हम लोगों ने निर्णय कर लिया है और सब प्रयत्न कर रहे हैं कि राशि की कमी नहीं होने दी जाए और सभी 1,000 से ज्यादा आबादी के गांवों को चार वर्षों के अंदर हम रूरल कनेक्टिविटी दे देंगे।

श्री सभापति: आप तो धन्यवाद दीजिए मंत्री जी को, सब काम हो गया।

श्रीमती प्रेमा करियप्पा: धन्यवाद मंत्री जी।

प्रो॰ राम देव भंडारी: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि कुल मिलाकर 26,829 हेबिटेशंस को जोड़ने का प्रस्ताव है, जिनमें बिहार में 1,164 प्रस्तावित हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार के 15 से 20 जिले हर वर्ष बाढ़ से आक्रान्त रहते हैं, जो भी सड़कें बनती हैं, चाहे 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के अंतर्गत ही क्यों न बनी हों, टूट जाती हैं। उनके मेंटीनेंस के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान किया जाएगा, ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ हर वर्ष इन सड़कों के टूटने की संभावना रहती है? क्या मंत्री जी या सरकार की ओर से कोई विशेष प्रावधान होगा, विशेष राशि की व्यवस्था होगी, जिससे कि उनका मेंटेनैंस अच्छी तरह से किया जा सके?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' से जो भी सड़कें बनेंगी, पांच वर्ष तक, बर्बादी के बाद भी, उनकी मेंटेनैंस करने के लिए प्रावधान किया गया है।

श्री सभापति: इसका मतलब है कि पहले वे सड़कें बर्बाद हों, तब जाकर वह बनेगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: और बाढ़ रोकने के स्थायी समाधान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां का सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, जब भारत-नेपाल का समझौता होगा और स्थायी समाधान के लिए व्यवस्था होगी, तब बाढ़ नहीं आएगी, फिर भी बाढ़ग्रस्त एरिया में पीसीसी सड़कें बनाने का प्रबंध किया गया है, जो बाढ़ से भी न टूटें और बर्बादी न हो।

श्री वसंत छोटेलाल चव्हाण: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितना काम आपने करने के लिए सोचा था टोटल, उसमें से कितने परसैंट पूरा हो गया है? यह जो रोड की जिस्ट आपने दी है, उसका टोटल काम कितना था और कितने प्रतिशत आप पूरा कर पाए हैं? दूसरे, महाराष्ट्र में 36,000 विलेजिस हैं, इन 36,000 विलेजिस में से आप सिर्फ 841 को कवर कर पाए हैं, जबकि हमारे राज्य की तरफ से यह मांग बराबर चली आ रही है। क्या आप इसकी तरफ अधिक ध्यान देंगे?

श्री सभापति: ध्यान देने के लिए कहा है, कह दीजिए ध्यान देंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, ध्यान दे रहे हैं और महाराष्ट्र का काम वैसे भी आगे है।